<u>आकाशवाणी केन्द्र शिमला</u>

23.12.2025 **15:00 बजे**

<u>उपराष्ट्रपति–एआई</u>

उपराष्ट्रपति सी.पी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत सर्वांगीण विकास और राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस–ए.आई. से संबंधित नीतियां और परियोजनाएं तैयार करने में वैश्विक स्तर पर सबसे सक्रिय देशों में से एक है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में आयोजित ए.आई विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन–ए.आई. महाकुंभ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ए.आई स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होना चाहिए। राधाकृष्णन ने कहा कि शुरूआत में ही ए.आई के बारे में जानकारी होने से छात्रों में बेहतर सोच का विकास होगा और समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर, समावेशी और तकनीकी रूप से सशक्त विकसित भारत की दिशा में ए.आई की महत्वपूर्ण भूमिका है।

<u>सुरेश कश्यप</u>

सांसद सुरेश कश्यप ने विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी–राम–जी विधयेक के माध्यम से योजना में किये गए बदलावों का स्वागत किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि मनरेगा में करीब 20 वर्षों के बाद ये सुधार हुआ है जिससे योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जायेगा।

बाईट : सुरेश कश्यप– सांसद शिमला

<u>विपक्ष बेवजह इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है मनरेगा की बात है जो पहले नरेगा होता था उसको बाद में मनरेगा का नाम दिया गया कि सितंबर 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी और अभी 20 साल पूरे होने के ऊपर इसमें जो व्यापक सुधारो की आवश्यकता थी उसको लेकर केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया में धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने कि मनरेगा में जो व्यापक स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा था जिस प्रकार से फर्जी जॉब कार्ड बनाए जा रहे थे समय के ऊपर पेमेंट नहीं हो रही थी और जिस प्रकार से प्रोडक्टिविटी स्कीम के माध्यम से होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही थी उसी को लेकर इसमें व्यापक सुधार अभी किए गए हैं।</u>

<u>चौहान–जी राम जी</u>

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार सृजन और व्यापक ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त निधि सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत एक लाख 51 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आबंटन प्रस्तावित किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्रमिकों को अब 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के

नाम पर एक बार फिर देश को गुमराह करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह योजना एक प्रगतिशील कदम है और काम उपलब्ध न होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के प्रावधान को भी और मज़बूत किया गया है।

वॉकथॉन

प्रदेश में चिटटे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत 26 दिसंबर को बिलासपुर में महा वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इस आयोजन को लेकर बिलासपुर में अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिमला, धर्मशाला और हमीरपुर के बाद अब बिलासपुर में यह चौथा बड़ा आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू प्रतिभागियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाएंगे।

बाइट : राजेश धर्माणी

एंटी चिट्ठा वॉकाथॉन बिलासपुर में रखा गया है। यह चौथा आयोजन है। उम्मीद है इसमें 15000 से ज्यादा युवा बिलासपुर के भाग लेंगे इसका मकसद यही है कि बच्चों में जागरूकता आए और समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वह भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो ताकि जो ड्रग पैडलर हैं उन्हें पकड़ा जा सके और सप्लाई चेन को तोड़ा जा सके।

राजीव सहजल

भाजपा नेता व पूर्व मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि प्रदेश से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्दे को भाजपा सांसदों ने लोकसभा व राज्यसभा में बार—बार मजबूती से उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण व रखरखाव में कोई कमी नहीं रखी है। सहजल ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया है कि बीते मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश में 50 हजार मीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुए जिसकी स्थायी बहाली के लिए केंद्र ने 5 सौ 13 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा केवल कीरतपुर—मनाली कॉरिडोर पर ही लगभग 5 सौ 44 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

विधानसभा सीट

चंबा जिला की चुराह विधानसभा सीट को अनारक्षित करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमण्डल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन भेजा है। लोगों का कहना है कि चुराह विधानसभा सीट पिछले 70 वर्षो से एक ही वर्ग के लिए आरक्षित है जिससे अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिल पा रहा है।

....